(पृष्ठ 8 का शेष)

परिवेश की ये विसंगतिया नजर नहीं आयी होंगी, ऐसा नहीं है। बात दरअसल यह है कि नैतिकता और मूल्यों के बारे में चिन्तित ये सज्जन खुद भी समाज की इन्हीं विसंगतियों की उपज हैं। प्रो. राजपूत जैसे लोगों का चिन्तन उस चौहद्दी के बाहर जा ही नहीं सकता जहां से बाहर निकलकर ही इन विसंगतियों को सुलझाया जा सकता है। वह चौहद्दी है लूट एवं शोषण पर टिकी आज के समाज की आर्थिक बुनियाद व इस पर खड़ी हुई समूची राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक इमारत, जिसे ध्वस्त किये बिना शिक्षा के ढांचे में किसी मूलभूत बदलाव की बात करना या तो काइयांपन हो सकता है या निरी मूर्खता। प्रो. राजपूत किस कोटि के हैं यह आकलन करना महत्वहीन है।

हां, प्रो. राजपूत एक दुविधा के शिकार जरूर हैं, जिसे व्यक्त करते समय वे नये पाठ्यक्रम की व्यावहारिकता पर खुद ही सवाल कर बैठते हैं। वह कहते हैं कि नये पाठ्यक्रम के जरिये सिखाये जाने वाले मूल्य प्रभावी होंगे या नहीं यह बच्चे के बाह्य परिवेश पर निर्भर करता है। लेकिन, इस बात से सिखाये जाने वाले मूल्यों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसलिए किसी स्तर पर इनका पाठ नहीं पढ़ाया जाये, इसे जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। इस पर तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि प्रो. राजपूत आप पूरे मनोयोग के साथ फल की चिन्ता किये बिना कर्म करते जाइये, दुविधा में पड़ेंगे तो न माया मिलेगी न राम मिलेंगे, न मुरलीधर। ●

(पृष्ठ 9 का शेष)

व्याख्या या कोई विधि वर्णित नहीं है। लेकिन, "भूमण्डलीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मददगार" शिक्षा के उद्देश्य की दृष्टि से इसकी संक्षिप्त व्याख्या ऐसे की जा सकती है :

पहला, विशिष्ट वर्ग के उन छात्रों का ई. क्यू और एस.क्यू उच्चस्तरीय होगा जो कम्प्यूटर-इंटरनेट की उच्च तकनीकी शिक्षा पूर्ण एकाग्रचित्त होकर अर्जित करेंगे और हर प्रकार के सामाजिक अन्याय, असमानता और शोषण से मुंह फेरकर पूर्णतया भावनाहीन और संवेदनहीन बनने को तत्पर होंगे। दूसरा, सामान्य वर्ग के उन छात्रों का एस. क्यू और ई. क्यू उच्च स्तरीय होगा जो राजभक्त और स्वामिभक्त होंगे, प्रभु वर्ग की सेवा अपनी नियति या पुराने पापों का फल मानकर करते रहेंगे और देशी-विदेशी लुटेरों की भूमंडलीय व्यवस्था की जड़ खोदने की दिशा में दिमाग को भटकने से रोकेंगे। ●

शिक्षा को उम्दा बाजारू माल बनाने के लिए बिड़ला-अम्बानी कम्पनी का नया फार्मूला

आदेश सिंह

बिड़ला और अम्बानी समूह को आप किस रूप में जानते हैं? विभिन्न किस्म के औद्योगिक उत्पादों के जरिये भारत के घरेलू बाजार को अपने कब्जे में रखने वाली एकाधिकारी पूंजी के स्वामियों के रूप में ही अगर अब तक आप जानते हैं तो आपकी जानकारी बासी पड़ चुकी है। कृपया ताजा जानकारी से अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा लें। बिड़ला-अम्बानी की ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी ने शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता के लिए एक नये उत्पाद का फार्मूला पास करने के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजा है। इस बात की सम्भावना शून्य के बराबर है कि फार्मूला रिजेक्ट कर दिया जाये।

शायद आपकी जानकारी में यह बात न हो कि शिक्षा विशेषज्ञ के रूप में बिड़ला-अम्बानी कम्पनी को मान्यता स्वयं प्रधानमंत्री ने ही दी थी। प्रधानमंत्री के विशेष निर्देश पर विगत 28 अगस्त 1998 को एक अधिसूचना जारी कर व्यापार एवं उद्योग परिषद का गठन किया गया था। उस समय इसके सदस्य थे—रतन टाटा, कुमारमंगलम बिड़ला, मुकेश अम्बानी, आर.पी. गोयनका, पी.के. मित्तल, सुरेश कृष्ण (टी.वी. एस.ग्रुप), एन.आर.नारायणमूर्ति (इनफोसिस वाले), नुस्ली वाडिया, ए.सी. मुथैया और डॉ. परविन्दर सिंह। परिषद के अध्यक्ष स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी थे। 13 नवम्बर 1999 को एक अन्य अधिसूचना के जरिये इसका पुनर्गठन किया गया, जिसके जरिये सदस्यों में कुछ बदलाव कर संजीव गोयनका, राहुल बजाज, एन. श्रीनिवासन, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव बृजेश मिश्रा को शामिल किया गया। इस परिषद के तहत छह ग्रुप बनाये गये जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा क्षेत्र, पूंजी बाजार, निजीकरण, अच्छा शासन आदि पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके लिए उन्हें सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय से अधिकतम सम्भव सहयोग और सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन भी दिया गया। 11 दिसम्बर 1999 को फिर इन छह ग्रुपों को बढ़ाकर आठ कर दिया गया और उनसे सलाह मांगी गयी। मुकेश अम्बानी और कुमारमंगलम बिड़ला शिक्षा के लिए गठित विशेष समूह के विशेषज्ञ बनाये गये।

इन धनकुबेर विशेषज्ञों ने भूमण्डलीकरण चश्मे और अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष-विश्वबैंक के 'स्टेथोस्कोप' से देश की उच्च शिक्षा की बीमारी का अध्ययन कर इलाज के लिए नुस्खे तैयार किये और "दवा का सैम्पल" जनवरी महीने में प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया है। सम्भावना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने में कोई अड़चन नहीं आयेगी और दवा को व्यापक स्तर पर उपभोग के लिए बाजार में जल्दी ही उतारा जायेगा।

हालांकि जो सिफारिशें भेजी गयी हैं, वे नयी नहीं हैं क्योंकि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में सीमित पैमाने पर इनका अमल पहले से ही जारी है। कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- एक निजी विश्वविद्यालय-विधेयक तैयार किया जाये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करे।
- विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली सरकारी सहायता धीरे-धीरे खत्म कर दी जाये।
- शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उपाय किये जायें।
- कानून बनाकर विश्वविद्यालयों-कालेजों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी जाये।
- प्राइवेट रेटिंग कम्पनियों से विश्वविद्यालयों के काम-काज की रेटिंग करवाई जाये।

ये सभी सिफारिशें भूमण्डलीकरण के मौजूदा दौर में देशी-विदेशी पूंजी की नयी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने के आदेशपत्र जैसे हैं जिन्हें अमली जामा पहनाने के लिए अब सिर्फ सरकारी मुहर की जरूरत बाकी है। शिक्षा क्षेत्र को देशी-विदेशी पूंजी के निवेश के लिए तैयार करने के लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा के बारे में "परम्परागत" सोच को बदला जाये। शिक्षा को अन्य उद्योगों जैसा दर्जा दिया जाये जिसमें सिर्फ लाभ-हानि के गणित पर पूंजीप्रवाह हो। शिक्षा के बारे में सोच बदलने का काम पिछले एक दशक से जारी है। भाड़े के शिक्षाविद, बाजारप्रेमी प्रोफेसर और मीडिया के कलमघिस्सू पश्चिमी देशों के उदाहरण दे-देकर इस काम में अपनी सारी ऊर्जा लगाये हुए हैं। एक मानसिकता तैयार की जा रही है कि शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व और समाज का विषय

न होकर एक बिकाऊ माल है।

इसके बाद अगला कदम है शिक्षा क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश की परिस्थितियां तैयार करना। यह काम भी चालू है। संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर सरकारी सहायताओं की राशि लगातार कम की जा रही है और खुद संसाधन जुटाने के फार्मूले के तहत प्रवेश से लेकर अन्त तक अध्ययन की विभिन्न सुविधाओं के लिए छात्रों से मोटी रकमें वसूल की जा रही हैं। स्थिति ऐसी सीमा तक पहुंचा देने का लक्ष्य है जब शिक्षकों-कर्मचारियों की तनख्वाहों तक के लिए सरकार अपने हाथ उठा दे। यानी, विश्वविद्यालय बीमार घोषित कर दिये जायें। तब उनके उद्धार के लिए देशी-विदेशी पूंजी के लिए मैदान पूरी तरह खाली हो जायेगा। वैसे, विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय बीमारी की हालत में आ भी चुके हैं। शिक्षकों-कर्मचारियों को कई-कई माह का वेतन नहीं मिल पा रहा है। नयी भर्तियां लगभग बन्द हैं। शिक्षकों की कमी की भरपाई के लिए शिक्षकों को ठेके पर पढ़ाने का काम दिया जा रहा है।

लेकिन, उच्च शिक्षा क्षेत्र में देशी-विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश में सबसे बड़ी बाधा विश्वविद्यालयों की "राजनीति" है। शिक्षक-कर्मचारी राजनीति चाहे जितनी नखदन्तविहीन हो चुकी हो, जब उनके आर्थिक हितों पर चोट पहुंचेगी, नौकरी पर बन आयेगी तो विरोध की आवाज उठनी स्वाभाविक है। महज फीसें बढ़ाने और सीटें घटाने के सवाल पर ही नहीं, इतिहास गवाह है कि व्यापक सामाजिक मुद्दों पर छात्रों-युवाओं के आन्दोलन सत्ता के लिए जबर्दस्त चुनौती बनते रहे हैं। बिड़ला-अम्बानी की बिरादरी इसीलिए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक पूंजी निवेश के लिए तब तक तैयार नहीं है जब तक कि परिसरों से राजनीति की हर सम्भावना को खत्म न कर दिया जाये। इसीलिए कानून बनाकर परिसरों की राजनीति पर रोक लगाने की सिफारिश की गयी है। विश्वविद्यालयों की रेटिंग करते समय रेटिंग कम्पनियां आर्थिक ब्यौरे के साथ-साथ इस मानक का खास ख्याल रखेंगी कि उस परिसर से "राजनीति" का कितना सफाया हुआ है।

प्रधानमंत्री कार्यालय अपने चहेते 'विशेषज्ञों' की भावनाओं और जरूरतों का विशेष ख्याल रख रहा है। अगले शैक्षणिक सत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रत्यक्ष निर्देशन में उच्च शिक्षा में "सुधार" की योजना फैसलाकुन मुकाम पर पहुंचाने का 'मास्टर प्लान' तैयार हो रहा है।

क्या शिक्षक-कर्मचारी और छात्र राजनीति इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है? ●

मथुरा में फीसवृद्धि के खिलाफ छात्राओं का आन्दोलन

एक स्वतःस्फूर्त विस्फोट जो भविष्य की आहट दे गया

आगरा मंडल के शिक्षाजगत में यह एक किस्म का भूचाल था जो कालेज छात्रों की फीस वृद्धि का मसला लिये उठ खड़ा हुआ था। महीना था नवम्बर-दिसम्बर का। न कोई राजनीतिक-सांगठनिक प्रश्रय, न ही योजनाबद्ध मोर्चेबन्दी, मथुरा की छात्राएं स्वतःस्फूर्त सड़कों पर निकल पड़ीं। लक्ष्य था उत्तर प्रदेश सरकार की लुटेरी शिक्षा नीति की मुखालफत। सरकार ने बीच सत्र में कालेजों के लाखों-लाख छात्रों पर अचानक शोषण का जाल फेंका था। सरकार के उस मनमाने फैसले से सीधे तौर पर अभिभावकों की जेब पर डाका डाला गया था। छात्राओं के दिमाग में यही बात कौंध गयी कि उनके संरक्षकों को लूटने के लिए सरकार का कदम निजी स्कूल प्रबन्धकों से भी ज्यादा घटिया और खतरनाक है। क्योंकि यदि राज्य अपने इस प्रयोग में कामयाब हो गया तो उनके लिए आगे की पढ़ाई-लिखाई मानो चने चबाने जैसी कर दी जायेगी।

उधर सरकार का फरमान जारी हुआ और इधर मथुरा शहर के कन्या महाविद्यालयों की छात्राएं मुट्ठी बांधकर सड़कों पर निकल पड़ी। यह ललकार कालेज प्रबन्धन के लिए कम, जिला प्रशासन की नजर में ज्यादा हैरतअंगेज और चुनौतीपूर्ण थी। आन्दोलन उठने पर दो-चार दिनों तक प्रशासन असमंजस की स्थिति में रहा। इसीलिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच उस रणनीति पर मतैक्य नहीं रहा कि आन्दोलन का आखिर सामना कैसे किया जाये। नतीजा पुलिस और प्रशासनिक अमले अलग-अलग दमन के स्फुट प्रयोग करने लगे। उससे छात्राओं को अपनी लड़ाई आगे ले जाने में थोड़ी आसानी भी हुई। उस दिन तो छात्राओं की संघर्ष-चेतना ने पूरे आगरा मंडल को ही झकझोर दिया जब मथुरा का होलीगेट अभूतपूर्व चक्का जाम और मानवश्रृंखला की गिरफ्त में आ गया। पूरे शहर की यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त हो उठी। लड़ाकू छात्राओं की मानव श्रृंखला और समाज में अभिभावकों, आम नागरिकों की भी साझेदारी जुड़ गई। पुलिस टुकड़ियां अपने अधिकारियों के साथ मौके पर जमी रहीं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि कोई सबल हस्तक्षेप करतीं। पुलिस अधिकारी मूकदर्शक बने रहे, छात्राओं की ललकार राज्य सरकार की बददिमागी पर बरसती रही। आनन-फानन में ही चौराहे पर सार्वजनिक मंच बना कर सभा की गई। विरोध प्रदर्शन अपने मकसद में पूरी हिम्मत से कामयाब रहा। प्रशासन हाथ मल कर रह गया। ऐसा मथुरा के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ था कि इतने बहादुराना अंदाज में महिलाओं ने शासन-प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारा हो।

मथुरा प्रशासन व प्रदेश सरकार के लिए यह आंदोलन इन अर्थों में भी अपना अलग सरोकार रखता था कि इस जिले से मंत्रिमंडल में चार मंत्री हैं जिनमें श्याम सुंदर शर्मा, सरदार सिंह, दो कैबिनेट स्तर के हैं। इस स्वतः स्फूर्त आंदोलन की मुखरता इन मंत्रियों की स्थानीय राजनीति में सीधे-सीधे खलल पैदा कर रही थी, सो इन चारों के कान अलग से खड़े हुए। पहले तो लखनऊ में गुपचुप कानाफूसियां चलती रहीं। मथुरा प्रशासन से पलपल के हालात की फोन पर सूचना ली जाती रहीं, लेकिन जब एक दिन छात्राओं ने आन्दोलन का रुख मोड़ते हुए होमगार्ड मंत्री श्यामसुन्दर शर्मा के स्थानीय आवास पर ही धावा बोल दिया, उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी को घर में कैद कर लिया तो प्रशासन की घिग्घी बंध गयी। हुआ यह कि इससे एक दिन पहले प्रशासन ने थोड़ी हिम्मत जुटा कर छात्राओं के साथ कड़ाई कर दी थी। दो-तीन छात्राओं को पीटा-घसीटा गया था। छात्राएं काफी उत्तेजित थीं। लड़ाई हिंसक हो उठी थी। उसी की प्रतिक्रिया था आंदोलन का नया चरण। छात्राओं ने मंत्री के घर में उनकी पत्नी को लखनऊ फोन मिलाने के लिए विवश कर दिया। फोन पर होमगार्ड मंत्री की छात्राओं से सीधे वार्ता हुई। धूर्ततापूर्वक उन्हें खोखला आश्वासन देकर मंत्री ने अपनी और अपने घर वालों की जान छुड़ाई। अब आंदोलन से मथुरा की कानून व्यवस्था का प्रश्न उठ खड़ा होने लगा था। लखनऊ में बैठे चारों मंत्री अपने गृहक्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।